से स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने उक्त याचिका को वापिस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते): (क) केन्द्रीय जांच ब्यरो ने सूचित किया है कि दिनांक 9.2.90 को पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना डकैती मामले के मुकदमें के केन्द्र को बदलने से संबंधित 1989 की स्थानान्तरण याचिका 53- भारत के महान्यायवादी बनाम बलवीर सिंह एवं अन्य-वापस लिये गये मामले के रूप मे उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी। महान्यायवादी द्वारा उक्त याचिका को वापस लिये जाने का उल्लेख तकनीकी कारणों से किया गया था।

(ख) उक्त डकैती के मुकदमे के केन्द्र को स्थानान्तरित करने के लिये पूर्वोक्त स्थानान्तरण याचिका भारत के तत्कालीन महान्यायवादी द्वारा दिनांक 20-2-89 को उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24-4-89 को अतिरिक्त न्यायाधीश की अदालत, नामित अदालत, लुधियाना के समक्ष उपर्युक्त मामले में कार्यवाही स्थगित रखने की स्वीकृति प्रदान की थी। चूंकि कुछ तकनीकी कारणों से उक्त याचिका को वापस लेना उचित पाया गया था, इसलिये भारत संघ के अनुदेश प्राप्त होने के बाद भारत के महान्यायवादी ने दिनांक 9-2-90 को उच्चतम न्यायालय में उक्त याचिका वापस लेने का उल्लेख किया और अदालत ने वापस लिये गये मामले के रूप में उक्त याचिका खारिज कर दी।

अन्य विवरण लोक हित में नहीं दिये जा सकते, क्योंकि मुकदमे पर कार्यवाही चल रही है।

भारत में अफीम का स्टाक

286. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अफीम का स्टाक इतना अधिक हो गया है कि अर्धन्यायिक अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को विवश होकर अन्य देशों से यह अनुरोध करना पड़ा है कि वे अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के लिये भारत से अफीम का आयात करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते): (क) और (ख) प्रश्न में यथा उल्लिखित अर्धन्यायिक अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग्स कन्ट्रोल बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। संभवतः यह संकेत अन्तर्राष्ट्रीय नार-कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड, वियना (आस्ट्रिया) के बारे में है।

भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यतः निर्यातोन्मुखी है। भारतीय अफीम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वैकल्पिक कच्ची सामग्री नामशः पोस्त, तृण (पापी-स्ट्रा) के सांद्रण से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में कमी आई है तथा इसके उत्पादन को कम करने के लिये भारत द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद भी इसके भण्डार मे वृद्धि हुई है। विश्व में स्वापक कच्ची सामग्रियों की सप्लाई भी अधिक है।

स्वापक कच्ची सामग्री के अधिक भण्डार; विशेष रूप से भारत में अफीम के बहुत बड़े भण्डार से संबंधित समस्या को, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड ने भारत को स्वापक कच्ची सामग्रियों के चिरकालित पारस्परिक सप्लाई-कर्ता देशों में से एक देश के रूप में माना है तथा जिसकी सहायता किये जाने की आवश्यकता है। इस धारणा को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (इकानामिक एंड सोशल काउन्सिल) के कई संकल्पों द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खपत करने वाले देशों से पारस्परिक सप्लाईकर्ता देशों को सहायता करने के लिये अनुरोध करने के साथ-साथ उन उत्पादनकर्ता देशों से अपने-अपने उत्पादन को केवल अपनी

घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित रखने का आग्रह किया गया है, जो हाल ही के वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आये थे।

Increase in the Cost of Beverage Concentrate Plant of Pepsi

287. KUMARI SUSHILA TIRIA : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article in 'the Business World' (dated 25th October, 7th November, 1989) on Pepsi Project;

(b) if so, what are the reasons for increase in the cost of beverage concentrate plant from Rs. 5.5 crore to Rs. 11 crore ; and

(c) whether it is a fact that Coca Cola's proposed plant at NOIDA was to cost Rs. 3.5 crore and if so, what precisely are the equipments Pepsi Projects are using to justify such a high cost?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to M/s. Punjab Agro Industries Corporation the increase in the project cost is due to the following reasons:—

(1) The investment in fixed assets such as land, equipment, plant and machinery and supporting infrastructural and ancillary facilities would be at higher levels.

(2) Since 1986, when the project was mooted, inflationary pressures have increased the costs substantially.

According to the application of Coca Cola their investment in buildings and plant and machinery was to be approximately Rs. 2.44 crores.

Export of Handloom Goods

288. SHRI M. VINCENT : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the value in rupees of handloom goods exported during the last two years;

(b) what steps are being taken to step up the export target;

(c) what measures have been taken for giving more financial assistance to handloom weavers to procure yarn ; and

(d) what steps are being taken by Government to provide adequate yarn at lower prices ?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) : (a) The exports of cotton handloom fabrics and made-ups increased from Rs. 237.63 crores in 1987-88 to Rs. 283.36 crores in 1988-89 representing an increase of about 19%.

(b) Keeping in view growth trends, a higher export target of Rs. 360 crores has been fixed for 1990-91 as against the target of Rs. 300 crores in 1989-90 for cotton handlooms. The Government have taken a number of steps to boost handloom exports such as sending trade delegations, conducting market studies and market researches, releasing advertisements in foreign trade magazines and distribution of publicity material, participation in exhibitions abroad, quality improvement of handloom products besides grant of Cash Compensatory Support etc.

(c) NABARD provides refidance facilities to State Cooperative Banks for financing *Inter-alia* production and marketing activites